RAJYA SABHA

Wednesday, 9th March, 2011/8 Phalguna, 1932 (Saka)

The House met at eleven of the clock,
MR. CHAIRMAN in the Chair.

MATTERS RAISED WITH PERMISSION

Problems faced by producers of documentary films and non-compliance of directions of the Supreme Court

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी (उत्तर प्रदेश): उपसभापति महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। दुनिया के सभी देशों में जो लघु फिल्में होती हैं, उन लघु फिल्मों के निर्माता, टेक्निशियंस और उनसे जुड़े हुए लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है। हमारे देश में हमारे देश की सरकार ऐसे हजारों लघु फिल्म निर्माताओं और उनसे जुड़े हुए लाखों लोगों को प्रोत्साहित करने की बात तो दूर है, उन पर प्रतिबंध लगाने का षड़यंत्र कर रही है। सर, हम सबको याद है कि पिछले 60 वर्षों से हम मूल फिल्म से पहले सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सरोकार से जुड़ी हुई सभी डॉक्यूमेंट्रीज सभी सिनेमा हॉल्स में देखते थे और उनका एक बहुत अच्छा संदेश देश में जाता था। लेकिन सूचना और प्रसारण मंत्रालय और नौकरशाही के निजी स्वार्थों की वजह से उन हजारों लघु फिल्म निर्माताओं, उनसे जुड़े हुए लाखों-लाख परिवार, टेक्निशियंस, फोटोग्राफर्स और कलाकारों को बेरोजगार करने का षड़यंत्र किया जा रहा है। उपसभापति महोदय, यह विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि देश में बारह हजार से ज्यादा सिनेमा हॉल्स में अब तक जो शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं वे फिल्मों से पहले सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों पर संदेशात्मक फिल्में देते थे। लेकिन सरकार ने अभी एक निर्णय किया है और उस निर्णय के तहत ऐसे जो छोटे प्रतिभावान निर्माता हैं, उन निर्माताओं की फिल्मों पर रोक लगाने के उद्देश्य से उन्होंने जो मल्टीप्लेक्स के मालिक हैं, उन पर दबाव डालने के उद्देश्य से उनसे कहा कि आप फिल्म डिविजन की फिल्म लेंगे और उसके अलावा इन निजी निर्माताओं की फिल्म नहीं लेंगे। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण चीज है कि सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत स्पष्ट निर्देश सरकार को है और सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश सरकार को दिया गया है।...**(व्यवधान)**...

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK (Goa): Sir, this is an issue for Special Mention and not for Zero Hour. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is permitted.

SHRI MUKHTAR ABBAS NAQVI: I know it is Zero Hour. This is a matter of public importance. ...*(Interruptions)*...

माननीय उपसभापति महोदय, मेरा यह निवेदन है कि इस देश के हजारों प्रतिभावान फिल्म निर्माताओं, कलाकारों और टेक्निशियंस को बेरोजगार होने से रोका जाए और सरकार को निर्देश दिया जाए कि जो व्यवस्था पहले से चालू है, उसमें फिल्म डिविजन अगर फिल्म बनाना चाहता है तो बनाए, लेकिन निजी निर्माताओं को भी फिल्म बनाने की अनुमति दी जाए और सुप्रीम कोर्ट के जो दिशा निर्देश हैं, उनका पूरा पालन किया जाए। धन्यवाद।

MISS ANUSUIYA UIKEY (Madhya Pradesh): Sir, I associate.

DR. BHARATKUMAR RAUT (Maharashtra): Sir, I associate.

श्री नंद कुमार साय (छत्तीसगढ़): महोदय, मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री वी.पी. सिंह बदनौर (राजस्थान): महोदय, मैं भी इससे अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

श्री संजय राउत (महाराष्ट्र): महोदय, मैं इससे एसोसिएट करता हूं।

Killing of social activist for exposing corruption in implementation of the scheme under MNREGA in Jharkhand

MS. MABEL REBELLO (Jharkhand): Sir, on 2nd March, one Niyamat Ali was murdered in Jerua village of Manika block of Latehar district. He was an activist and he was doing social audit for NREGA. Sir, on 2nd March, some 7-8 persons came to his house, dragged him out and hit him on his chest and beat him very badly. They had no intention of killing him. That shows that it is the contractors, officers and others who were involved. Sir, the ex-BDO, without doing NREGA work and without getting the work done, had sent an advisory note to the post office and the post office without verification paid something like Rs. 2 lakh odd to that contractor. When this activist Niyamat Ali complained, this BDO, his * and contractor went and beat him up and killed him. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The word * is unparliamentary. ...*(Interruptions)*...

MS. MABEL REBELLO: Sir, the benefits of NREGA, instead of going to the beneficiaries, to the poor, is going to the officers, to the contractors and their henchmen. My request is that if NREGA continues like this, it is of no use to the people for whom it is meant for. The money should really go to the people and not to the officers and others. Sir, in Gumla district in the year 2006-2007-2008, officers and NGOs have taken away 12 crores of rupees and I have complained twice on this count. There is a report against the senior officers. In spite of that, nothing has happened to the senior officers. But only NGOs and smaller level officers are in the jail. I request that the Government of India should direct the Government of Jharkhand to take strict action against the then DC, DDC, Director NREGA and put them behind bars...*(Interruptions)*... This amount of Rs. 12 crores that has gone, that has been siphoned off in Gumla district, it should be recovered from the senior officers, that is, DC, DDC and all these people. You know, even today, after 4 years, Rs. 12 crores is reflected as unspent in the accounts of DC Gumla. The money should be recovered and it should be put in the Government treasury. This is my request...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The entire House associate with the matter raised by the hon. Member, Ms. Mabel Rebello...*(Interruptions)*... Nothing will go on record. Please sit down. Nothing will go on record.

---

*Expunged as ordered by the Chair.